

## हमिचल प्रदेश संसदीय सचवि अधनियिम, 2006

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हमिचल प्रदेश उच्च न्यायालय (HP HC) ने हाल ही में हमिचल प्रदेश संसदीय सचवि (नयुक्त, वेतन, भत्ते, शक्तियों, वशिषाधिकार और संशोधन) अधनियिम, 2006 को रद्द कर दिया है, जिसके तहत राज्य सरकार को [वधिनसभा सदस्यों \(MLAs\) को मुख्य संसदीय सचवि \(CPS\)](#) के रूप में नयुक्त करने की शक्ति दी गई थी।

- न्यायालय ने फैसला दिया कि HPPSA, 2006 राज्य वधिनमंडल की वधायी क्षमता से परे है, जिससे यह कानून असंवैधानिक हो जाता है।
- HPPSA, 2006 से अनुच्छेद 164 (1-A) का उल्लंघन होता है, जिसके तहत कैबिनेट का आकार और उसकी संरचना सीमति की गई है।
  - अनुच्छेद 164 (1-A) के अनुसार किसी राज्य में मंत्रपरिषद में मुख्यमंत्री सहति मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी।
- न्यायालय ने कहा कि CPS द्वारा औपचारिक शक्तियों के अभाव के बावजूद मंत्रियों के समान कार्य करने के साथ समान सुवधिएँ, सरकारी फाइलों तक पहुँच और नरिणय लेने में भागीदारी का लाभ उठाया।
- इसके अतरिकित्त ["लाभ के पद"](#) के तहत सार्वजनिक पद धारकों को अतरिकित्त लाभ प्राप्त करने के क्रम में अपने पद का उपयोग करने से रोका गया है। संवैधानिक प्रावधान द्वारा समर्थति न होने पर CPS जैसे पदों का सृजन इसका उल्लंघन है।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि मंत्रियों और संसदीय सचवियों के बीच अंतर आभासी होने के साथ संवैधानिक नयिमों के वरिद्ध है।
- हमिचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को CPS नयुक्तियों तुरंत समाप्त करने तथा इनके सभी संबंधति वशिषाधिकार रद्द करने का आदेश दिया।
- इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, पंजाब, गोवा और असम जैसे राज्यों में संसदीय सचवि के पदों के सृजन को लगातार असंवैधानिक करार देते हुए मंत्रपरिषद में 15% की अधिकतम सीमा का हवाला दिया है।

और पढ़ें: [महिलाओं की न्यूनतम वविाह आयु 21 वर्ष करने हेतु वधियक](#)